साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज शहीद-ए-आज़म भगतसिंह

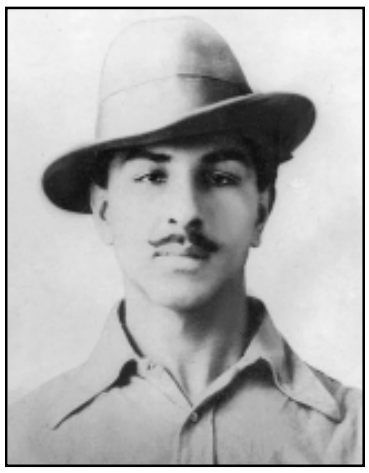

शहीद-ए-आज़म भगतसिंह की 117 वीं जयंती 28 सितम्बर के अवसर पर, उन्हें क्रांतिकारी अभिनन्दन, लाल सलाम प्रस्तुत करते हुए, उनका ये लेख प्रस्तुत है। ये विचार आज उससे कहीं मौजूं हैं जब 95 साल पहले, जून 1928 के किरती के अंक में पहली बार प्रकाशित हुए थे।

1919 के जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के बाद, ब्रिटिश सरकार ने, साम्प्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरु किया। इसके असर से 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में साम्प्रदायिक दंगों पर लम्बी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिन्दू-मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखवाकर दंगों को रोकने के यत्न किये। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किये। यह लेख, इस समस्या पर शहीद भगतसिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है। संपादक

भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी, दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिन्दुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मार-काट इसलिए नहीं की गयी कि फलां आदमी दोषी है, वरन् इसलिए कि फलां आदमी हिन्दू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिन्दू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिन्दुस्तान का ईश्वर ही मालिक है।

ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का भविष्य बहुत अन्धकारमय नजर आता है। इन 'धर्मों' ने हिन्दुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है। और हमने देखा है कि इस अन्धविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिन्दू, मुसलमान या सिख होता है, जो अपना दिमाग ठण्डा रखता है, बाकी सब के सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डण्डे-लाठियां, तलवारें-छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर-फोड़-फोड़कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिये जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन 'धर्मजनों' पर अंग्रेजी सरकार का डण्डा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। यहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे साम्प्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिन्दुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो 'समान राष्ट्रीयता' और 'स्वराज्य-स्वराज्य' के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाये चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मान्धता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है? लेकिन ऐसे नेता जो साम्प्रदायिक आन्दोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे

बहुत ही कम हैं, और साम्प्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आयी हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है।

दूसरे सज्जन जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था। आज बहुत ही गन्दा हो गया है। यह लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे-मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौव्वल करवाते हैं। एक-दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक बहुत कम है जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शान्त रहा हो। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, साम्प्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, साम्प्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि 'भारत का बनेगा क्या?'

जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहां थे वे दिन कि

स्वतन्त्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और कहां आज यह दिन कि स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है। बस यही

तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है। जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गयी, कल गयी वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी हैं कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है।

यदि इन साम्प्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दीं। उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गयी थी। असहयोग आन्दोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास-सा हो गया जिससे आजकल के बहुत से साम्प्रदायिक नेताओं के धन्धे चौपट हो गये। विश्व में जो भी काम होता है, उसकी तह में पेट का सवाल

शेष पेज चार पर

पुलिस की रिश्वतखोरी पर डीजीपी शत्रुजीत का अंकुश

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। हर महकमे की तरह पुलिस में भी रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। पुलिस महकमे में यह भ्रष्टाचार आम सा हो चुका है, विजिलेंस टीमें गाहे बगाहे रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ती भी रहती हैं। शत्रुजीत कपूर के डीजीपी बनने के समय हमने मज़दूर मोर्चा के अंक में लिखा था कि जब विजिलेंस वाले किसी रिश्वतखोर थानेदार या हवलदार को पकड़ सकते हैं तो उस थाने का एसएचओ या उस हलके का एसीपी, डीसीपी क्यों नहीं पकड़ सकता। क्या ये काम विजिलेंस वालों का ही है? एसएचओ को नहीं पता कि उसका मातहत हवलदार क्या कर रहा है? एसीपी-डीसीपी को नहीं मालूम कि उनके मुलाजिम क्या कर रहे हैं, क्या उन तक शिकायतें नहीं पहुंचतीं?

शत्रुजीत कपूर जो विजिलेंस प्रमुख से अब राज्य पुलिस प्रमुख बन गए हैं उनसे सवाल है कि क्या अब भी इन रिश्वतखोरों को विजिलेंस वाले ही पकड़ेंगे या जिला पुलिस अपनी काली भेड़ों को पकड़ेगी। हाल ही में शत्रुजीत कपूर ने एक पत्र के जरिए फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक अगर कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर भी जिम्मेदार होगा। हर थाने में सुपरवाइजरी अफसर (पर्यवेक्षण अधिकारी) एसएचओ होता है वह अपने मातहतों का सुपरवाइजरी अफसर होता है। इसी तरह एसीपी थानों का सुपरवाइजर है, उनके ऊपर डीसीपी और पुलिस आयुक्त, ये सभी अपने मातहत अधिकारी, कर्मचारी के सुपरवाइजरी अफसर हैं। आसान शब्दों में अगर चौकी का कोई कर्मचारी रिश्वत लेते या भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता है तो चौकी इंचार्ज, एसएचओ, एसीपी और डीसीपी भी जिम्मेदार होंगे। अब तक ये सारे बच जाते थे। यानी इससे पहले जितने भी रिश्वतखोर

डीजीपी शत्रुजीत कपूर

विजिलेंस ने पकड़े हैं उसके चौकी इंचार्ज, एसएचओ या बड़े अधिकारी को नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन यह फरमान जारी होने के बाद जब पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते आईएमटी चौकी के एएसआई को पकड़ा गया तो आईएमटी चौकी इंचार्ज, एसएचओ थाना सदर बल्लभगढ़ और एसीपी को भी नोटिस जारी किया गया।

यह समझने वाली बात है कि एक एएसआई की इतनी औकात नहीं है कि बिना ऊपर वालों की जानकारी के वह अकेले दस हजार, पचास हजार रुपये ले ले। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किसी को थाने में जबरदस्ती बैठ कर टॉर्चर करता रहे, मारता रहे और उस पर प्रेशर बनाता रहे। अगर सब लूटमार एएसआई या हवलदार को ही करनी है तो उसके ऊपर बैठा अफसर क्या कर रहा है।

एसएचओ, एसीपी सो रहे हैं या उन्होंने ने अफीम खा रखी है क्या, जो उन्हें अपने मातहतों के काम नजर नहीं आते। हर एसीपी पर गिने चुने दो से तीन थानों का चार्ज है और उस पर भी वह नजर नहीं रख सकें तो उनका फायदा क्या है।

बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है कि वो जो रिश्वत ले रहा है वो अपने बूते नहीं ले रहा, ऊपर तक हिस्सा जाता है। अकेले उसकी हिम्मत और औकात नहीं है कि वह अकेला पचास हजार रुपये हजम कर जाए। चौकी इंचार्ज, एसएचओ और एसीपी सबको पता होता है कि थाने या चौकी में कौन-कौन सी दरख्वास्त आई हुई हैं, क्या-क्या जुर्म हुए हैं और कौन-कौन बैठा रखे हैं, सब कुछ उनकी जानकारी में होता है। हां, शाम को बहीखाता जरूर मिला लेते हैं कि कितना माल आया और कितना गया।

महकमे में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए इस तरह का फरमान जारी करने पर डीजीपी शत्रुतजीत कपूर बधाई के पात्र हैं। इस फरमान की पालना करते हुए सीपी राकेश कुमार आर्य ने बाकायदा चौकी इंचार्ज, एसएचओ और संबंधित एसीपी को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। अगर इस व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाता है तो थाने वाले भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी।

अगर सुपरवाइजरी अफसर भी नजर रखने लगेंगे और पकड़ने लगेंगे तो पूर्णतया तो नहीं लेकिन काफी हद तक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, अभी तक जो खुला खेल चल रहा था वह इसी रूप में तो नहीं चल पाएगा और भ्रष्टाचार को पकड़ने का सारा जिम्मा केवल विजिलेंस पर नहीं रह जाएगा। डीजीपी के इस रुख से जनता को थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना हो सकती है।

पैसे के बल पर जांच आगे नहीं बढ़ने दे रहा फर्जी इंजीनियरिंग डिग्री धारक पदम भूषण

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार के गढ़ नगर निगम में मन माफिक काम करने के लिए अधिकारी सिर्फ जनता से ही धन नहीं लेते हैं बल्कि सहकर्मी की काली करतूतों को दबाने-छिपाने के लिए उससे भी मोटा सुविधा शुल्क वसूलने में पीछे नहीं रहते। ताजा उदाहरण इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे कार्यकारी अभियंता पदम भूषण का है। सीएम विंडो पर जून में की गई शिकायत को नगर निगम के अधिकारी तीन महीने से दबाए बैठे है जबकि पंचकूला स्थित राज्य मुख्यालय मे बैठे आयुक्त शहरी स्थानीय निकाय विभाग निगम आयुक्त को कई बार चिट्ठी लिख कर जांच रिपोर्ट तलब कर चुके हैं।

नगर निगम के वर्तमान कार्यकारी अभियंता पदम भूषण सहित एसई ओमबीर आदि कई बड़े अधिकारी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए और एआईसीटीई से अमान्य इंजीनियरिंग संस्थानों से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर नौकरी हासिल कर रहे हैं। इन अधिकारियों की डिग्री मान्य या अमान्य होने का मामला नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की बीच बीते करीब सात साल से चर्चा में है।

इसकी जानकारी सेक्टर 76 निवासी सिद्धार्थ कादियान को हुई तो उन्होंने 08 मई 2023 को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पदम भूषण की इंजीनियरिंग की डिग्री की वैधता की जांच कराने और गलत

नकली इंजीनियर पदम भूषण

पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की थी। सीएम विंडो की जानकारी होते ही सक्रिय हुए पदम भूषण ने सहकर्मियों को खिला पिला कर जांच दबवा दी। इधर जवाब नहीं मिलने पर सिद्धार्थ कादियान ने एक माह बाद फिर रिमाइंडर भेजा।

आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगमायुक्त को पत्र लिख कर पदम भूषण की डिग्री की वैधता की जांच करा कर दो सप्ताह में अपनी टिप्पणी के साथ भेजने का आदेश दिया। नगर निगम के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार पदम भूषण ने यह पत्र तत्कालीन निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया तक पहुंचने ही नहीं दिया, पत्र नहीं पहुंचाने के लिए उसने संबंधित को मोटा सुविधा शुल्क चुकाया था।

सीएम विंडो के पेंडिंग मामलों की समीक्षा के दौरान सिद्धार्थ कादियान की मई की कंप्लेंट पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 12 सितंबर को एक बार फिर निगमायुक्त को पत्र लिख कर दो सप्ताह में अपनी टिप्पणी के साथ जांच रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार भी पदम भूषण ने मोटा थैला सरका कर आयुक्त के पत्र को दबवा दिया है ताकि जांच न हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास खुद भ्रष्ट मातहतों से घिरी हैं जो उन तक सच्चाई पहुंचने ही नहीं देते। यदि निगमायुक्त सच में ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने चारों तरफ लगी भ्रष्टाचारियों की बाड़ को उखाड़ फेकें, बेईमान अधिकारियों को ठिकाने लगाएं और कमान मजबूती से अपने हाथ में संभालें।

सरकार की फ्लैगशिप योजना होने के कारण सीएम विंडो पर लंबित शिकायत अधिकारी के कॅरियर पर धब्बा लगा सकती है।

यानी फर्जी डिग्री के बल पर नगर निगम में जूनियर इंजीनियर से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पद तक पहुंचने वाले पदम भूषण की निगम के अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर खुद को बचाने की कवायद कहीं मोना ए श्रीनिवास को महंगी न पड़ जाए। मुख्यालय से भेजी गई चिट्ठियों का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।